JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# नैनीताल जनपद के पर्वतीय ग्रामीण महिलाओं के जीवन पर उज्जवला योजना का प्रभाव : एक संक्षिप्त अध्ययन

डॉ0 संतोष कुमार आर्य,
असिस्टेंट प्रोफेसर , वाणिज्य विभाग
एम० बी० राज० स्नात० महा० हल्द्वानी
नैनीताल,उत्तराखंड
•••••••••
डॉ0 बसंत नेगी,
असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
राजकीय स्ना0 महा० रानीखेत,
अल्मोड़ा,उत्तराखंड

भारत जैसे विकासशील देश में ऊर्जा एक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि किसी देश के आर्थिक स्तर की वृद्धि आर्थिक कारकों को भी उसी अनुपात में बढ़ावा देती है, विशेष रूप से ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में। फिर भी, कुछ राज्यों में अभी भी न केवल उस प्रकार की ऊर्जा खपत की कमी का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि खाना पकाने के उद्देश्य के लिए भी ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन खाना पकाने की ऊर्जा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन ने कई लोगों को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के तहत रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक उपभोग करने के लिए उकसाया है। यह पत्र आर्थिक प्रभाव के आकलन के पहलू में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' योजना का वर्णन करता है। लकड़ी में खाना पकाने से जो धुआं उठता है वह महिलाओं को सांस और सिरदर्द जैसी कई तरह की बीमारियों से घेर लेता है। महिला प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की इन समस्याओं को देखते हुए 1 मई 2016 को 'स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन' के नारे के साथ शुरू किया गया था। उज्ज्वला योजना एक धुंआ रहित भारतीय ग्रामीण जीवन की परिकल्पना करती है। यह योजना एलपीजी के उपयोग को बढ़ाएगी और स्वास्थ्य संबंधी विकारों, वायु प्रदूषण और वनों की कटाई को कम करेगी क्योंकि भारत में लगभग 41 प्रतिशत परिवार अभी भी खाना पकाने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। इस योजना की रूपरेखा 2015 में ही 'हार मान लेना' के रूप में तैयार की गई थी और आर्थिक रूप से समृद्ध एलपीजी कनेक्शन धारकों को प्रधानमंत्री द्वारा सब्सिडी छोड़ने का अनुरोध किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप 1.13 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी, महाराष्ट्र सब्सिडी छोड़ने में सबसे आगे रहा।

डब्लू0 एच0 ओ0 के अनुसार लकड़ी से निकलने वाला धुआं उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना एक घंटे में 400 सिगरेट जलाने से होता है। इस संगठन की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवाश्म ईंधन से खाना पकाने के कारण हर साल 5 लाख से अधिक महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस योजना से महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और इसने सामाजिक–आर्थिक कारकों में वर्गीकृत आर्थिक विचारों के साथ बयानों की गणना की जो व्यवसाय, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य और आर्थिक कारकों से संबंधित हैं जो पी0एम0य0वाई0 योजना के साथ ग्रामीण पहलुओं के आधार पर आयात, खपत और मांग को इंगित करते हैं। अंत में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित माननीय मंत्रियों द्वारा उजागर की गई प्रतिक्रिया भी इस शोधपत्र में ली गई है।

**कीवर्ड..... पर्वतीय ग्रामीण परिवार , एलपीजी, महिला सशक्तिकरण, पीएमयूवाई, जीवाश्म ईंधन, ।**

## परिचय

लकड़ी में खाना पकाने से जो धुंआ उठता है वह महिलाओं को सांस और सिर दर्द जैसी कई तरह की बीमारियों से घेर लेता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बीपीएल परिवार की महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2019 तक देश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले 5 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित करना था। अप्रैल 2018 में 3.5 करोड़ से अधिक मुफ्त कनेक्शन वितरित किए गए। उज्ज्वला योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 तक अपने लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया है। डब्लू0 एच0 ओ0 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 5 लाख से ज्यादा महिलाओं की मौत जीवाश्म ईंधन से होती है और लाखों महिलाओं को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार का प्रत्येक कनेक्शन पर 1600 जबकि प्रत्येक नए कनेक्शन की लागत रुपए 3100 या रुपए 3200 रुपये का खर्च आता है। . इसके बाद लाभार्थी परिवार को पहले सिलेंडर और गैस स्टोव के लिए 1500 रुपए मिलेगी। उज्ज्वला योजना न केवल सामाजिक–आर्थिक उत्थान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। इस योजना के तहत 1200 करोड़ रुपये शामिल हैं। पहले चरण में सरकार ने कुल रु. 8,000 करोड़ किया गया था।यह ज्ञात है कि दुनिया की एक तिहाई से अधिक आबादी केवल घरेलू उपयोग के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग करती है। उज्ज्वला योजना के विस्तार से जलाऊ लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई कम होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की ताकत भी मिलेगी। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 2020–21 के बजट में इस योजना के तहत एक करोड़ और लोगों को कनेक्शन देने की घोषणा की है. जिससे इस योजना का और विस्तार किया जाएगा।

## इस योजना के बारे में (पी0एम0यू0वाई)

यह योजना हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राथमिक संसाधनों की कमी और उनके निरीक्षण के तहत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बनाए गए उपयोगकर्ताओं के बीच हानिकारकता के कारण लागू की गई थी। यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की योजना है जिसका नाम है 'प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना' का लक्ष्य है और इसका लक्ष्य 2019 तक अगले तीन वर्षों के भीतर गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल) के तहत रहने वाले लोगों को पांच करोड़ मुफ्त खाना पकाने का एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। यह रुपये की मौद्रिक आपूर्ति के रूप में योगदान देता है। 2011 की सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना के माध्यम से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए उनकी स्थिति के मूल्यांकन द्वारा प्रत्येक परिवार (बी0पी0एल) को 1600। सरकार इस योजना द्वारा महिला सशक्तिकरण के साथ–साथ गरीबों के आर्थिक स्तर को समृद्ध करने का लक्ष्य बना रही है और उन्हें स्वास्थ्य दक्षता प्रदान करना। इस योजना से कई ग्रामीण लोग जो खाना पकाने के लिए हानिकारक ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, उसी तरह शहरी और अर्ध–शहरी लोगों को भी लाभान्वित किया जाएगा जो रसोई में एल0पी0जी का उपभोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। योजना का उद्देश्य बीपीएल से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कुशल खाना पकाने की ऊर्जा प्रदान करना है

## अध्ययन के उद्देश्यः

- पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे काम कर रही है उज्ज्वला योजना।
- उज्ज्वला योजना के वास्तविक लाभों को जानने के लिए।
- यह जानने के लिए कि उज्ज्वला योजना द्वारा पर्वतीय ग्रामीण महिलाओं को कितना लाभ दिया गया है।
- उज्ज्वला योजना की वर्तमान स्थिति जानने के लिए।

## साहित्य की समीक्षाः

उज्ज्वला योजना और महिलाओं के जीवन में इस योजना के प्रभाव के संबंध में शोधों द्वारा विभिन्न लेखों और शोध पत्रों का अध्ययन किया गया है।

रमन देवी (2017) ने अपने लेख ''प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाः मुद्दे और चुनौतियां'' में डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य पर जीवाश्म ईंधन के प्रभाव का अध्ययन किया।

अमोस, टी और श्री देवी, एन (2017) ने अपने लेख ''भारत सरकार की प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लिए एक आर्थिक आकलन'' में सामाजिक–आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर इस योजना के प्रभाव पर चर्चा की।

**योजना का उद्देश्यः–**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके और उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा की जा सके। महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पेड़ों की बिक्री को रोकना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और पर्यावरण की बिक्री को बनाए रखना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

**योजना की विशेषताएंः–**

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों को 1600 रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 5 करोड़ गैस कनेक्शन प्रदान करेगी। .
- गैस और रिफिल के खर्च पर ईएमआई की सुविधा भी दी जाएगी. यह ब्याज मुक्त ऋण होगा।
- कनेक्शन केवल महिलाओं के नाम पर जारी किए जाएंगे।

**उज्ज्वला योजना और महिला सशक्तिकरणः–**

स्वतंत्र भारत में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक महत्वपूर्ण कारक है। महिला सशक्तिकरण का देश की ऊर्जा अर्थव्यवस्था से गहरा संबंध है। यह योजना पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है। इस योजना के तहत महिलाओं को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन मिलेगा। इस योजना के और विस्तार के लिए प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायतों की शुरुआत की गई। इसमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी के सुरक्षित और सतत उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, देश भर में 87,876 एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया गया। फरवरी 2018 में, हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने भविष्य में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत उपयोगी होने के लिए राष्ट्रपति भवन में एलपीजी पंचायत का आयोजन किया।

**पी0एम0यू0वाई की वर्तमान स्थितिः–**

उज्ज्वला योजना सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, इसलिए इस योजना के तहत लगभग 8.3 करोड़ गरीब परिवारों को लाभान्वित किया गया है। यह भी कहा कि कोरोना महामारी के चलते योजना के लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उज्जवला योजना पेट्रोलियम गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जा रहा है जिनका नाम 2011 की जनगणना में बी0पी0एल कार्ड में है।

**विवेचना**

शोधपत्र की सत्यता के लिए हमने उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के कई छोटे–छोटे गांव में लगभग 200 लोगों पर सर्वे किया, जिसमें हमने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के आर्थिक एवं सामाजिक पहलू पर प्रश्न पूछे सर्वेक्षण से इस बात की जानकारी प्राप्त हुई की लगभग 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं 6 लोगों का या उनके परिवार के 6 से अधिक लोगों का खाना बनाती हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के इस कार्य को आसान बना दिया है, क्योंकि रसोई गैस का उपयोग करने से महिलाओं की सुविधा बढ़ गई है, जबकि रसोई गैस के उपयोग से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में मुख्यता आज भी लकड़ी, कृषि अपशिष्ट एवं गोबर के उपले आदि का इस्तेमाल किया जाता था। अतः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को एक बड़ी उपलब्धि की तरह देखा जा सकता है। एल0पी0जी के इस्तेमाल से महिलाओं के समय की भी बचत हो रही है जब ग्रामीणों से इस योजना के कारण खाना पकाने में हो रही सुविधा के बारे में पूछा गया तो पता चला कि लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण इस तथ्य को स्वीकार करके काफी खुश थे, कि वह अब पहले की तुलना में आसान हो गया है। इस योजना में गरीब लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है क्योंकि लकड़ी का या उपलों का खाना बनाने में जो धुआं निकलता है उससे महिलाओं को कई तरह की बीमारियां हो जाया करती हैं, किंतु रसोई गैस का इस्तेमाल करने से काफी हद तक इन बीमारियों पर अंकुश लगा है। निसंदेह स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में खाना पकाने से बेहतर स्वास्थ स्थितियां मिलती हैं। सर्वे के दौरान इस तथ्य को लगभग 80 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने पर्वतीय ग्रामीण लोगों के सामाजिक जीवन स्तर को उठाने में गति प्रदान की है, किंतु जैसे ही हम इन ग्रामीणों के आर्थिक पहलू पर नजर डालते हैं तो पता चलता है की अधिकांश घरों में एल0पी0जी सिलेंडर भरने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यह लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं पैसा नहीं होने के कारण यह अपना सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं। वर्तमान में ऐसा देखने को मिला है कि रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस समय इन ग्रामीण लोगों तक गैस सिलेंडर 1073 रुपए से 1100 रुपए तक पहुंच रहा है। उसके बाद ढुलाई अलग से देनी पड़ती है या खुद सिलेंडर को सिर पर लाद कर ले जाना पड़ता है। महंगाई ने इन

ग्रामीणों की कमर तोड़ दी है पर्वतीय ग्रामीण इलाकों में पहले से ही रोजगार की कमी है, ऊपर से बढ़ती महंगाई के कारण यह लोग सिलेंडर भरवाने में अपने आपको असहाय महसूस कर रहे हैं। पूछताछ से यह भी पता लगा कि इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने काफी लंबे समय से एल0पी0जी सिलेंडर भराया ही नहीं या यूं कहें कि एल0पी0जी कनेक्शन मिलने के बाद से बमुश्किल दो या चार बार ही सिलेंडर भरा पाए हैं, तथा लकड़ी व उपलों पर वापस आने के लिए विवश है । अतः यदि ऐसा कहा जाए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इन गरीब लोगों के सामाजिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सक्षम है, किंतु गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई ने इनकी आर्थिक स्थिति को इतना कमजोर कर दिया है कि यह फिर से पुराने ढर्रे पर चलने को विवश हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

**निष्कर्ष :–**

उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो इस योजना की सफलता के लिए ग्रामीण गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित है, केंद्र सरकार। समय–समय पर मूल्यांकन करके अपने लक्ष्यों को संशोधित किया है। अध्ययन के दौरान यह निष्कर्ष निकला कि यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना ने महिलाओं को सशक्त बनाया, उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाया और स्वस्थ जीवन का मार्ग प्रशस्त किया और पेड़ों की कटाई में भी कमी आई है जिससे प्रकृति को भी बहुत लाभ हुआ है। मैंने पूर्व में कई योजनाओं का अध्ययन किया है लेकिन इस योजना के अध्ययन में इसके इतने सकारात्मक पहलू हैं कि नकारात्मक पहलुओं का स्थान नगण्य रह जाता है। वास्तव में, मुझे लगता है कि यह योजना ''एक तीर से कई लक्ष्यों को मारना'' कहावत को पूरी तरह से पूरा करती है। क्योंकि इस योजना से गरीब ग्रामीण महिलाओं को जितना फायदा हुआ है, उससे कम हमारी प्रकृति को फायदा नहीं हुआ है।

**सुझावः –**

समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का मूल्यांकन किया गया है, सुधारों और लक्ष्यों को फिर से परिभाषित किया गया है, इसलिए इस योजना में अधिक सुझाव के लिए कोई जगह नहीं है, फिर भी इस योजना के कुछ निम्नलिखित सुझाव हो सकते हैंः–

- इस योजना के लाभों के बारे में ग्रामीण महिलाओं को और अधिक जागरूक करने के लिए, इसके लिए एक ही गांव से एक महिला का चयन किया जाना चाहिए। जो वहां के हालात से पूरी तरह वाकिफ हैं.
- इस योजना में छह सिलिंडरों की संख्या निःशुल्क या कम से कम दो माह प्रति सिलेंडर की दर से तय की जाए।
- यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्रामीण महिलाएं जीवाश्म ईंधन का उपयोग बिल्कुल भी न करें।

**संदर्भ**


- अदिति, आर. (2016, 16 मई)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इंडियन एक्सप्रेस। नई दिल्ली, भारत।
- बैंक, डब्ल्यू. (2013)। समावेशन मायने रखता हैः साझा समृद्धि के लिए फाउंडेशन। वाशिंगटन डीसीः विश्व बैंक।
- ब्यूरो, पी.आई. (2016, 20 दिसंबर)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल महिलाओं को 1. 22 करोड़ से अधिक नए एलपीजी कनेक्शन जारी। नई दिल्ली, भारत।
- घरेलू वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तथ्य पत्रक छ'292 अपडेट किया गया। (2016, फरवरी)। तथ्य पत्रक छ'292 अद्यतन किया गया।
- घोष, एस.के. (2020)। एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बाद उज्ज्वला योजना को ग्रामीण भारत का लाइववायर बनाना (अंक संख्या 73)। इकोरैप, एसबीआई।
- एम बंसल, आर.पी. सैनी, डी.के. खातोद, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के क्षेत्र का विकास– एक समीक्षा
- अक्षय और सतत ऊर्जा समीक्षा, खंड 17, पृष्ठ 44–53, पोस्ट किया गयाः 2013।
- एस. अग्रवाल, एस. कुमार, एम.के. तिवारी–प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऊर्जा नीति के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली, खंड 118, पीपी। 455–461,2018।
- india-gov-in/spotlight/pradhan&mantri&ujjwala&yojana
- www-petroleum-nic-in